

# योजना के परिणामों का मैदानी स्तर पर हो मूल्यांकन: राज्यपाल

मोपाल (काप्र)

राज्यपाल मंगभाई पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना के परिणामों का मूल्यांकन मैदानी स्तर पर किया जाए। बैचिंट और छूट रहे व्यक्तियों और क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं की पहुँच को सफलता का पैमाना माना जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुँचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मानिटरिंग का भी यही लक्ष्य होना चाहिए।

श्री पटेल आज जनजातीय प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन दो सत्रों में किया गया प्रथम सत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग के समीक्षा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, आयुष मंत्री इंद्र रिंग परमार घोड़द थे। द्वितीय सत्र में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग के दौरान सिक्कल सेल प्रभावितों की अधिक संख्या बाले के प्रसव पूर्व जांच के साथ जैरेटिक कार्ड उपलब्ध हो। रोगी और वाहक को तेक्काल उत्तिर और व्याधि उपलब्ध हो। वाहक और रोगी नियमित रूप से औषधि लें। इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग के लिए सामुदायिक जन जागृति के प्रयास आवश्यक हैं। जरूरी है कि घर-घर जाकर इस संबंध में सीधा संपर्क और संवाद कायम किया जाए।



प्रदान की जाए। जांच का कार्य तेज गति से किया जाए। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसव के 72 घन्टों के भीतर जांच हो। इस संबंध में विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जाना चाहिए। चिन्हित वाहक और रोगियों को प्राथमिकता के साथ जैरेटिक कार्ड उपलब्ध हो। रोगी और वाहक को तेक्काल उत्तिर और व्याधि उपलब्ध हो। वाहक और रोगी नियमित रूप से औषधि लें। इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग के लिए सामुदायिक जन जागृति के प्रयास आवश्यक हैं। जरूरी है कि घर-घर जाकर इस संबंध में सीधा संपर्क और संवाद कायम किया जाए।

उन्होंने मैदानी अमलों का संवेदीकरण कर, उनके माध्यम से जन जागरण के प्रयासों के लिए निर्देश दिए हैं।

## सिक्कल सेल उम्मलून में आयुष की पद्धतियों का तुलनात्मक परीक्षण हो

श्री पटेल ने आयुष विभाग की चर्चा के दौरान कहा कि सिक्कल सेल रोग प्रबंधन और उपचार में होयोपैथी, आयुर्वेद और योग की भूमिका के संबंध में विभाग द्वारा किए जा रहे अनुसंधान का तुलनात्मक परीक्षण भी कराया जाए। पॉयलट जिलों की सभी तहसील के वाहक और रोगी अध्ययन में सम्मालित हो। इसकी

सुनिश्चितता की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक सिक्कल सेल उम्मलून प्रयासों को व्यापकता प्रदान करने में आयुर्वेद की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मेंडिकल कॉलेज इंडॉर के टांसप्यूजन विभाग को केन्द्र सरकार के साथ इंटरेंस घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सिक्कल सेल प्रभावितों को जैरेटिक कार्ड प्रदान करने के साथ ही व्यापकता देखने के लिए अपने सुरक्षा एवं व्यक्तियों को चिह्नित करने पर फोकस हो। प्रयास, ऐसे क्षेत्रों, समुदाय और व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक प्रबाधन और संशोधन और नवाचार पर केन्द्रित होने चाहिए। राज्यपाल

सिंह परमाल ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय कर सिक्कल सेल जन जागृति के प्रयासों को विस्तारित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि समस्त महाविद्यालयों में सिक्कल सेल के संबंध में चिकित्सकों के द्वारा जानकारी दिए जाने के लिए परियोग दिए जाएं।

बैठक के दूसरे सत्र में राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विकसित भारत का मूलाधार सबका साथ और सबका विकास है। इसी के लिए सरकार की योजनाओं का निर्णय किया गया है। योजना की मांशा की सफलता क्रियान्वयन की दृष्टि और दिशा पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अमला सरकार के चालक है। अमला जितना सजावा और सक्रिय होगा। सरकार भी उतनी ही गतिशील होगी। इसकार्य एवं आवश्यक है। श्री पैरियोग से लेकर जमीनी स्तर तक का अमला योजना की मांशा के प्रति संवेदनशील हो।

मॉनिटरिंग की प्रणाली धरातल पर छूट गए, व्यक्तियों, क्षेत्रों को चिह्नित करने पर फोकस हो। प्रयास, ऐसे क्षेत्रों, समुदाय और व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक प्रबाधन और संशोधन और नवाचार पर केन्द्रित होने चाहिए। राज्यपाल

श्री मंगभाई पटेल ने जनजातीय कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और विभागीय योजनाओं पर चर्चा में कहा कि विभाग द्वारा पी.वी.टी.जी जिलों में नए जिले शामिल किये जाने चाहिए। पेसा ग्राम सभाओं के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के

प्रो. त्रिपाठी राजा शंकर शाह छिन्दवाड़ा के कुलगुरु नियुक्त राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगभाई पटेल ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कुलगुरु के पद पर प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त किया है। महात्मा गांधी चित्रकृत ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकृत, जिला सतना (म.प्र.) के विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय के प्रोफेसर एवं अधिकारी आवश्यक है। प्रो. त्रिपाठी का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो, के लिए रहेगा।

लिए महाराष्ट्र राज्य के प्रावधानों का अध्ययन कर विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए।

# मप्र विस अगले मानसून सत्र तक होगी पेपरलेस

मोपाल (काप्र)

मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र, 2025 तक पेपरलेस किया जाए। इसके लिए विधानसभा में नेशनल ई-विधान परियोजना (नेवा) लागू की जाए।

उन्होंने इस परियोजना के लागू होने से पहले विधानसभा सदस्यों को भी इसकी पर्याप्त जानकारी देने को भी निर्देश दिये हैं। श्री तोमर आज विधानसभा में नेवा हाउस कमेटी की बैठक के संबोधित कर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जल्द से जल्द लागू करने की बात कर रही है। उन्होंने अब तक 23 प्रदेशों के 25 सदनों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी का जिला सत्र तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरामीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी का जिला सत्र तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरामीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी का जिला सत्र तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरामीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी का जिला सत्र तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरामीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी का जिला सत्र तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरामीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी का जिला सत्र तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरामीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी का जिला सत्र तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरामीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी का जिला सत्र तक सहयोग लिये जाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयरामीय ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए एप्रेल के प्रदेशों को नोडल ट्रैनिंग देकर रहा।

उप मुख्यमंत्री गणेशदेव देवका ने ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए एप्रिल में एप्यार्डी क